ISBN:978-81-926009-4-9

वर्तमान आर्थिक मुद्दें एवं चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी

6 जनवरी 2018

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ.के.पी.अहिरवार

संपादक
डॉ.तुलसी राम दहायत

आयोजक

शास. कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह (मप्र.)

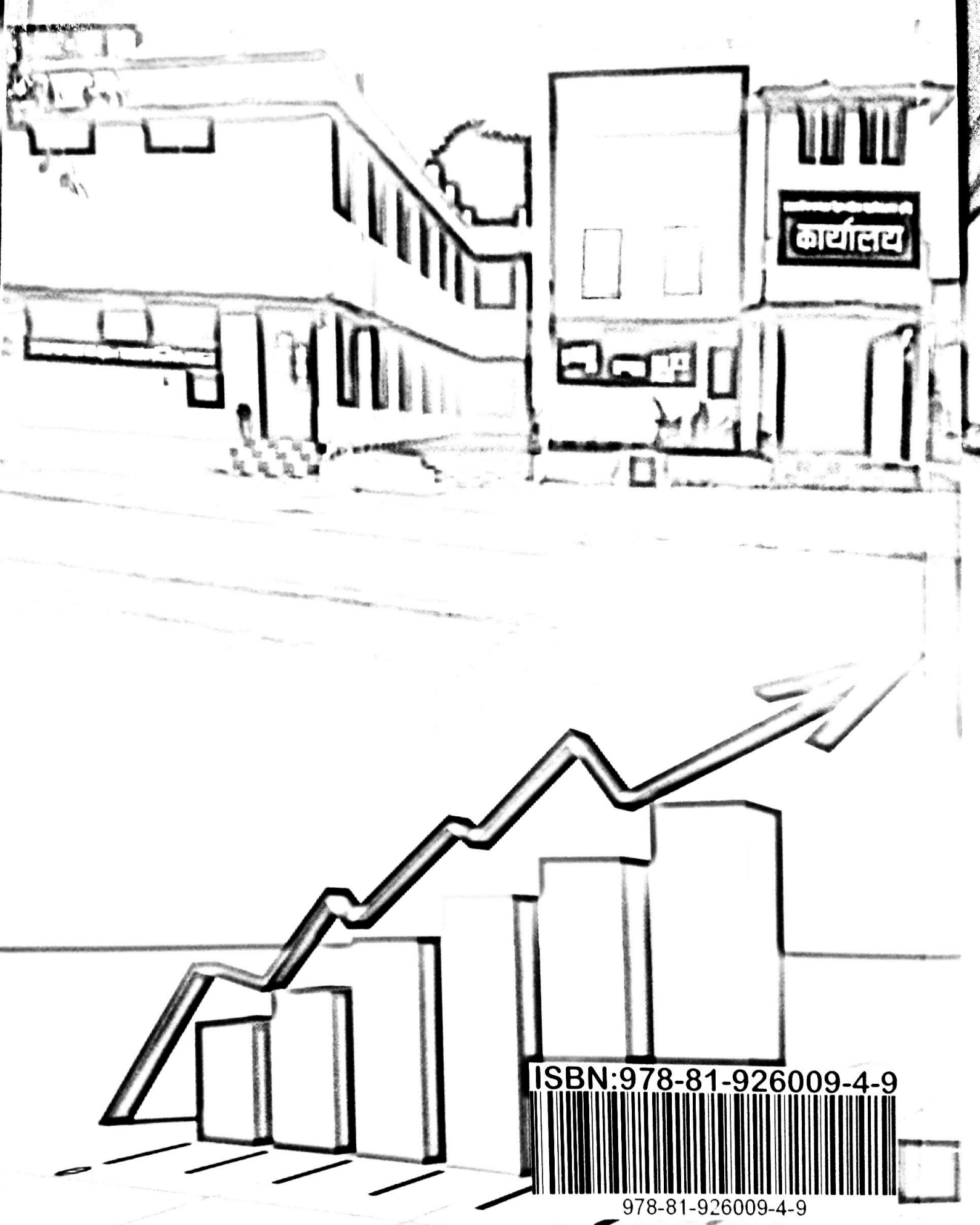

ISBN:978-81-926009-4-9

978-81-926009-4-9

Mask Printers &Suppliers,Kandya Complex 30, Sarafa Bajar Sagar (M.P.)

राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी

वर्तमान आर्थिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ

6 जनवरी 2018

आयोजक

शास. कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह (मप्र.)

प्राचार्य एवं संरक्षक

डॉ.के.पी.अहिरवार

संपादक

डॉ.तुलसीराम दहायत

समन्वयक

डॉ.डी.के.नेमा

ISBN:978-81-926009-4-9
Mask Printers&Suppliors,
Kandya Complex
30,Sarafa Bajar Sagar (M.P.)

कम्प्यूटर एवं तकनीकी सहयोग
सौरभ खरे
Composing& Designing By
P.K.PRINTERS Damoh (M.P.)

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृ.क्र.
1	भारतीय आर्थिक विकास मे डॉ. अबेडकर की भूमिका	डॉ.के.पी.अहिरवार	16
2	Indian economics growth in dollors; Strategies, radical remedies of golden crown jewel Medical tourism ?	*Dr. S. K. Bhatnagar, Director.*	19
3	IMPACT OF COST OF CULTIVATION ON FORMERS INCOME (Special Reference to Damoh District)	Dr.Tulsiram Dahayat Dr.Keshav Tekam	26
4	IMPLEMENTATION OF GOOD AND SERVICE TAX IN INDIA: PROSPECTS AND CHALLENGESDr. Vinod Sen, Dr. Anand Sugandhe	**Dr. Vinod Sen, Dr. Anand Sugandhe**	31
5	TREND OF URBANIZATION AND CHALLENGES IN BHOPAL	Dr.Kusum Mathur,&Seema Yadav.	38
6	Impact of fiscal sector reforms on Small Scale Industries	*Dr. Pooja Chaturvedi Dr. Atul Loomba Prof. (Dr.) N.C. Jain	43
7	"A Study of Working capital analysis of industry in M.P. with special reference to HEG Ltd Mandideep"	Dr. Preeti Shrivastava, Dr. Prof. N.C. Jain	48
8	Rural Electrification And Agriculture in Damoh District	Dr. Ramesh Athiya	56
9	A Socio Legal Study of Farmer's Interest Transition to Legal Rights	Mr. Shailendra Pachori	61
10	Challenges in Agriculture development for the Indian economy	Dr. BASANTI MATHEW MERLIN	66
11	RURAL TOURISM AND SUSTAINABLE LIVELIHOOD	Poonam Mishra	71
12	Demonetization and its Impact on Indian Society	Dr. Mamta Awasthy	77
13	IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE INDIAN ECONOMY	Ramesh Prasad Aharwal	80
14	Study of Electric Energy Management for a Machine System	P.L. Jain[1] and Santosh Kumar Jain[2]	83
15	मुद्रारहित लेनदेन : भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती	डॉ. हरिनारायण विश्वकर्मा	86
16	जुन्नारदेव मे कृषि विकास की चुनौतियाँ	डॉ. कुसुम माथुर,नविता राजुरकर	90
17	पावरलूम उद्योग में श्रम कल्याण की आवश्यकता	श्री राजेश काले	95
18	भारतीय औद्योगीकरण के क्षेत्र में महिला उद्यमी की भूमिका	देवी सिंह ठाकुर	98
19	मध्यप्रदेश में सोयाबीन फसल की उत्पादकता	प्रभाक्षी तिवारी	101
20	मध्यप्रदेश मे गन्ने की आधुनिक खेती, आज की आवश्यकता एक अध्ययन	डॉ.विनोद काले	105
21	"भारत में विमुद्रीकरण एक अध्ययन"	डॉ0 गजेन्द्र कुमार रावत,डॉ.अनिल जैन	108
22	गरीबी और आर्थिक विकास	जया अहिरवाल	112
23	विमुद्रीकरण (कम नगद अर्थव्यवस्था की ओर कदम)	डॉ. कीर्ति शुक्ला[1], डॉ.ए.के.पाण्डेय[2],	115
24	"भारत मे रोजगार नियोजन की संभावनाएँ"	डॉ. क़मर इज़हार	120
25	भारत मे गरीबी व जनांकिकीय परिवर्तन	श्रीमती मीना तिवारी	123
26	"ग्रामीण गरीबी और उसके प्रभाव"	डॉ. नीता ठाकुर	127
27	परम्परागत जल स्रोत्र एवं संकट	मनोज कुमार वर्मा एवम् डॉ0 प्रभाकर मिश्रा	132
28	मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी योजना का कियान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रभाव'	डॉ. पूजा तिवारी	134
29	गरीबी : एक चुनौती	शाहीन परवीन (अतिथि विद्वान)	137
30	**भूमंडलीकरण के भंवर में समकालीन समाज**	डॉ. मुदिता प्रवीण श्रीवास्तव	140
31	**बेरोजगारी एक विचारणीय मुद्दा**	**डॉ. अवधेश कुमार जैन एवं डॉ.डी.के.नेमा**	142
32	वर्तमान आर्थिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ वस्तु एवं सेवाकर (जी. एस. टी.)	*विद्यानन्द पाण्डेय डा0 वी0पी0 उनियाल	143

मुद्रारहित लेनदेन : भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती

डॉ. हरिनारायण विश्वकर्मा
अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)

सारांश– भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का अंश अधिक होने के कारण यह कहा जा सकता है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी विशेषताएं एवं सीमाएं होती हैं, लेकिन उसमें विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। मुद्रारहित लेनदेन के बारे में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कठिनाईयां जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे सफल नहीं बनाया जा सकता। आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ रहा है और अपने देश के विकास के लिए हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है। मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए सरकार ने काफी प्रतिबद्धता दिखाई है, अब जरूरत है कि हम उस कार्य को आगे बढाये, और सरकार के इस कदम को सफल बनाएं। पिछले वर्ष नोटबंदी के बाद मुद्रारहित लेनदेन मुद्रा रहित लेनदेन में काफी तेज गति से वृद्धि की है, लेकिन अभी भारत में इसका अनुपात देखा जाए तो मुद्रारहित लेनदेन करने वालों की संख्या 5 फीसदी से भी कम है। यह काम थोडा कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, बस प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा।

आधार वाक्य– मुद्रारहित लेनदेन, मुद्रारहित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना– पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार ऊपर से 1 रूपया भेजती है, लेकिन आम आदमी के पास उसका सिर्फ 15 पैसा पंहुच पाता है, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ जाता है। मुद्रा के इस लीकेज का प्रमुख कारण अधिकांश राशि का नगदी के रूप में प्रवाहित होना है। इस समस्या के समाधान का कारगार उपाय अर्थव्यवस्था में नगदी की मात्रा में कमी करना हो सकता है। वर्तमान केन्द्रीय सरकार इस काम को आगे बढाने की इच्छुक है। वास्तव में नगदी रहित लेनदेन वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय मामलों के जानकार तो यह भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में भारी धन की मौजूदगी अनेक समस्याओं का कारण है, एवं इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें नगदी का कम से कम इस्तेमाल हो। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदी के प्रवाह का प्रबंधन एक गंभीर समस्या बना हुआ है, क्योंकि देश में परिचलित मुद्रा में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा लेनदेन नगदी में होता है। मुद्रा प्रबंधन के साथ–साथ उसे छापना भी बहुत खर्चीला है। आरबीआई के मुताबिक मुद्रा के छापने में 2009–10 में 2800 करोड़ की लागत आई। इसके अलावा नगदी के भंडारण, परिवहन, नकली नोटों की जांच, एवं सुरक्षा आदि पर भी अत्यधिक व्यय करना पडता है। यदि अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से मुद्रा रहित लेनदेन बढ़ता है, तो प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रूपये की बचत होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रारहित लेनदेन– भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है। हर कठिनाई को तेजी से पार करते हुए विकास के नए लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, लेकिन कैशलैस की डगर में बहुत सारी बाधाएं है, जिन्हें पार करना उतना आसान नहीं है, जितना कि प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के दो पहलू हैं–एक शहरी क्षेत्र एवं दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि मुद्रारहित लेनदेन की राह आसान है भी लेकिन दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 के आकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या का 69 फीसदी अब भी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है, साथ ही भारत में कुल गावों की संख्या 6 लाख 50 हजार से भी ज्यादा है इन आकडों से पता चलता है कि भारत गावों का देश है, या भारत गावों में बसता है। गावों का विकास ही सही मायने में भारत का विकास है, जब तक गावों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं हो जातीं तब तक भारत का विकास नहीं होगा। रही बात मुद्रारहित लेनदेन की तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुद्रारहित लेनदेन की राह अभी बहुत ही टेढी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कई ऐसी समस्याएं हैं, जिनके चलते मुद्रारहित लेनदेन की ओर बढ पाना आसान नहीं है, उन विभिन्न समस्याओं को पहले दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

मुद्रारहित लेनदेन– मुद्रारहित लेनदेन का सीधा सा अर्थ है, पैसों का लेनदेन इलेक्ट्रानिक सिस्टम से होना, अर्थात् कोई भी लेनदेन मुद्रा की भौतिक उपस्थिति में न होकर इलेक्ट्रानिक माध्यम से होता है तब उसे मुद्रारहित लेनदेन (कैशलेस ट्रान्सेक्शन) कहते हैं।

मुद्रारहित लेनदेन का महत्व/लाभ– आज के परिवर्तनशील समय में किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने विभिन्न प्रकार की नई समस्याए सामने आ रही है, जिनमें से मुद्रा के माध्यम से लेनदेन की भी भी एक है। इन समस्याओं को देखते हुए दुनिया के कई देश मुद्रारहित लेनदेन की ओर बढ रहे हैं। जिस कारण मुद्रारहित लेनदेन का महत्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने भी पिछले वर्ष नोटबंदी के कदम से इस काम का श्रीगणेश कर दिया है और लगातार मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए प्रयासरत है। इस महत्व को देखते हुए मुद्रारहित लेनदेन के कुछ प्रमुख फायदे निम्नलिखित हैं–

1 अपराधिक गतिविधियों में कमी– मुद्रारहित लेनदेन का एक सबसे बडा फायदा यह होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के माध्यम से संचालित होने वाली विभिन्न अपराधिक गतिविधियां आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों आदि को फंडिग बंद हो जाएगी।

2 भ्रष्टाचार पर रोक संभव– भ्रष्टाचार आज प्रत्येक देश के गले की फांस बना हुआ है। इसका एक कारण मुद्रा के माध्यम से लेनदेन भी है यदि अर्थव्यवस्था में होने वाले लेनदेन मुद्रारहित हो जाए तो भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी।

3 कालेधन पर लगाम– अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भौतिक मात्रा ज्यादा होने के कारण जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना स्वभाविक है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण लेनदेन मुद्रारहित होगें तो कालेधन की समस्या का सवाल ही नहीं

उठेगा।

4. नकली नोटों की रोकथाम– नकली नोटों की समस्या तो सिर्फ मुद्रा की भौतिक उपस्थिति के चलन के कारण ही उत्पन्न होती है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं में से एक है, इसलिए नकली नोटों की रोकथाम के लिए मुद्रारहित लेनदेन का महत्व अत्यधिक बढ जाता है।
5. जीवन स्तर में सुधार– यदि व्यक्ति अपने सभी छोटे एवं बडे लेनदेन डिजिटल के माध्यम से करेगें अर्थात् हर व्यक्ति का बैंक में खाता होगा तो यह अपने आप में गर्व की बात होगी जिससे व्यक्ति की जीवन शैली में बदलाव होगा उसके जीवन स्तर में सुधार होगा।
6. मंहगाई कम करने में मदद– अर्थव्यवस्था में मंहगाई जैसी समस्याएं आम हैं, मंहगाई को कम करने के लिए हर देश की सरकार प्रयत्नरत रहती है। मुद्रारहित लेनदेन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढती मंहगाई को कम करने में मदद मिल सकती है।
7. सुरक्षा की भावना का विकास– मुद्रारहित लेनदेन मुद्रा को लाने और ले जाने से जुडी हुई सभी पेरशानियों से राहत दिला सकता है। जिस कारण व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना का विकास होता है।
8. कर चोरी मुश्किल होगी– नगदी के बिना किये गये लेनदेनों को आसानी से ट्रेक किया जा सकता है, इसलिए इन पर कर का भुगतान अनिवार्य रूप से करना पडेगा जिससे करचोरी संभव नहीं हो सकती। इस दृष्टि से भी मुद्रारहित लेनदेन का महत्व बढ जाता है।
9. खर्च को ट्रैक करना– मुद्रारहित लेनदेन माध्यम से होने वाले सभी लेनदेनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, और खर्चों का हिसाब भी आसानी से रखा जा सकता है।

मुद्रारहित लेनदेन के लिए आवश्यक साधन/उपकरण– मुद्रारहित लेनदेन को करने विभिन्न आवश्यक दशाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना मुद्रारहित लेनदेन संभव नहीं हो सकता है, अतः इसके लिए प्रमुख आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं–

1. आईटी नेटवर्क– मुद्रारहित लेनदेन की पहली प्राथमिकता यह है कि अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ आईटी नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मुद्रारहित लेनदेन संभव नही हैं।
2. कम्प्यूटर/मोबाईल– मुद्रारहित लेनदेन के लिए चाहिए कि अर्थव्यवस्था में इसके लिए आवश्यक सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे कम्प्यूटर, मोबाईल, इंटरनेट, आदि अत्यन्त आवश्यक हैं इनके बिना डिजिटल लेनदेन नहीं हो सकता।
3. बैंक खाता– मुद्रारहित लेनदेन के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले व्यक्ति का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, जिसमें से उस लेनदेन के लिए आवश्यक कटौती हो सके।
4. नेट बैंकिंग/मोबाईल बैंकिंग– मुद्रारहित लेनदेन के लिए व्यक्ति को अपने बैंक खाते से संबंधित नेट बैंकिंग या मोबाईल बैंकिंग की सुविधा चालू करवानी पडती है। जिसमें उसे एक आईडी एवं पासवर्ड बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वह मुद्रारहित लेनदेन के लिए कर सकता है।
5. क्रेडिट/डेबिट कार्ड– आज प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। क्रेडिट/डेबिट कार्ड से मुद्रारहित लेनदेन को आसानी से किया जा सकता है।
6. पीओएस मशीन– मुद्रारहित लेनदेन के लिए पीओएस (प्वाइंट ऑन सेल) मशीन के माध्यम से और भी आसानी से किया जा सकता है, सरकार को जगह जगह पर इन मशीनों की व्यवस्था करवानी चाहिए।
7. डिजीटल वालेट– इसके माध्यम से मुद्रारहित लेनदेन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाईल में एप डाउनलोड करना होता है, इस पर अपने आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से कैशलैस पेमेंट आसानी से किया जा सकता है।
8. अन्य पेमेंट गेटवे– मुद्रारहित लेनदेन के लिए आज अर्थव्यवस्था में कई माध्यम उपलब्ध हैं जैसे यूनीफीड पेमेंटस् इंटरफेस, एयरटेल मनी, पेटीएम आदि जिनके माध्यम से मुद्रारहित लेनदेन आसानी से किया जा सकता है।

मुद्रारहित लेनदेन में बाधक तत्व– मुद्रारहित लेनदेन तब बिल्कुल आसान है, जब इसके लिए चाही गई आवश्यक दशाएं उपलब्ध हों, लेकिन इन दशाओं के आभाव में मुद्रारहित लेनदेन संभव नहीं हो सकता, कुछ प्रमुख तत्व जो मुद्रारहित लेनदेन के मार्ग में बाधक होत है, निम्नलिखित है–

1. निरक्षरता– साक्षरता मुद्रा रहित लेनदेन के मार्ग में सबसे बडी बाधा है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति के लिए मुद्रारहित लेनदेन करना आसान नहीं है, यदि भारत की बात की जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता 75 प्रतिशत है, जिसमें से महिला साक्षरता मात्र 62 प्रतिशत ही है। इन आंकडों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि मुद्रारहित लेनदेन के मार्ग में साक्षरता बहुत बडी बाधा है।
2. आधारभूत सुविधाओं की कमी– भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अभी भारत में मुद्रारहित लेनदेन के लिए

आवश्यक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, मोबाईल, आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। एक आंकडे के अनुसार भारत में कुल आबादी का मात्र 27 प्रतिशत इंटरनेट यूजर्स हैं, स्मार्टफोन केवल 17 फीसदी लोगों के पास हैं।

3. सीमित बैंकिंग सेवाएं– भारत में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिनमें किसी भी बैंक की कोई शाखा नहीं है, जिस कारण वहा के लोग बैंक से सीधे जुडे हुए नहीं हैं, और यह मुद्रारहित लेनदेन के मार्ग में बहुत बडी बाधा है।
4. तकनीकि अज्ञानता– मुद्रारहित लेनदेन के लिए तकनीकि ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तकनीकि अज्ञानता के कारण मुद्रारहित लेनदेन में कई कठिनाईयों का सामना करना पडता है।
5. विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त चार्जेस– मुद्रारहित लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले उपभोक्ता से इसके लिए विभिन्न प्रकार के चार्जेस वसूल करते हैं, कभी कभी ये चार्जेस बहुत ज्यादा होते है, जिनके चलते व्यक्ति इस झझट से बचना चाहते हैं।
6. साईबर अपराध का भय– मुद्रारहित लेनदेन में सबसे बडा खतरा साईबर अपराध का रहता है, कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा किया जा रहा लेनदेन असुरक्षित न हो, जिसके चलते वह मुद्रारहित लेनदेन से बचना चाहता है।
7. अरूचि– मुद्रारहित लेनदेन भी व्यक्तियों की रूचि पर निर्भर करता है, कई कारणों से व्यक्ति इसमें रूचि कम लेते हैं, जो इस मार्ग में बडी बाधा है।
8. साख का प्रचलन– भारत की आधे से ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जिस कारण गांवों में लेनदेन के लिए साख का चलन हो जाता है, जो मुद्रारहित लेनदेन की राह में बाधक है।

भारत में मुद्रारहित लेनदेन को सफल बनाने हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास– भारत की बात की जाए तो वर्तमान सरकार मुद्रारहित लेनदेन को लेकर गंभीर दिख रही है, और वह यह चाहती है कि देश कैशलेस की ओर बढे। सरकार के द्वारा पिछले वर्ष नोटबंदी जैसा कदम उठाकर यह साबित भी कर दिया था, और सरकार तब से लगातार मुद्रा रहित लेनदेन को बढावा देने के लिए प्रयासरत है, इस दिशा में सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रयास किये जा रहे है–

1. बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि– मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है, देश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है, साथ ही हर व्यक्ति को बैंक से जोडने के लिए कई योजनाएं जैसे जनधन योजना चलाई जा रहीं हैं।
2. क्रेडिट/डेबिट/रूपे कार्ड जारी करना– बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड/रूपे कार्ड एवं उनकी साख को देखते हुए क्रेडिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं, जो मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए बहुत ही कारगार कदम है।
3. पीओएस मशीनों का विस्तार– मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पीओएस मशीनें भी लगवाई जा रही हैं, जिससे मुद्रारहित लेनदेन को आसान एवं सुविधाजनक बनाया जा सके। सरकार ने बैंकों को देश में 3 लाख पीओएस मशीनें लगाने का निर्देश दिया है।
4. लकी ड्रॉ जैसी योजनाएं– मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए सरकार एवं विभिन्न निजी कंपनियां लकी ड्रॉ जैसी योजनाएं चला रही हैं, जिनका फायदा समय–समय पर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिस कारण उपभोक्ता मुद्रारहित लेनदेन की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
5. विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना– मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए सरकार एवं निजी कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे डिस्काउंट, बीमा, वॉय वन गेट वन फ्री जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहीं हैं।

मुद्रारहित लेनदेन के समय बरती जाने वाली सावधानियां– वैसे तो मुद्रारहित लेनदेन अत्यन्त सरल एवं सहज है, मात्र एक क्लिक से आप हजारों का लेनदेन कर सकते हैं, लेकिन बढते साईबर अपराधों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मुद्रारहित लेनदेन पूर्णतः सुरक्षित है, अन्य चीजों की तरह इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं जिनको ध्यान में रखते रखकर इस लेनदेन को हम आसान बना सकते हैं, अतः मुद्रारहित लेनदेन के समय विभिन्न सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए–

1. मुद्रारहित लेनदेन के बारे में पहले से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
2. बैंक खाता संबधी जानकारी गोपनीय रखें।
3. कार्ड संबधी डाटा ऑनलाइन सेव न करें।
4. सुरक्षित लिंक का इस्तेमाल करें।
5. नए ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ कार्ड ऑन डिलेवरी जैसे ऑप्सन न चुनें।
6. मोबाइल ट्रेकिंग ऑप्सन हमेशा चालू रखें।

मुद्रारहित लेनदेन को गति देने हेतु आवश्यक सुझाव– भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप एवं विभिन्न समस्याओं एवं मुद्रारहित

लेनदेन के लिए आवश्यक दशाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुद्रारहित लेनदेन की राह आसान बनाने के लिए अभी सरकार को बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. रणनीति बनाने की आवश्यकता– मुद्रारहित लेनदेन की राह आसान नहीं है, इसके लिए सरकार को एक रणनीति के तहत अंजाम देना होगा, सरकार को सबसे पहले इसकी राह में आने वाली प्रमुख बाधाओं को चिन्हित करना होगा एवं उनको दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे, तब कभी इसकी मंजिल पर पंहुचा जा सकता है।
2. आधभूत सुविधाओं का विस्तार– मुद्रारहित लेनदेन के लिए आधारभूत सुविधाओं जैसे इंटरनेट, कम्प्यूटर, मोबाईल आदि के विस्तार की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना यह आसान नहीं है।
3. आईटी नेटवर्क का विस्तार– देश में सबसे पहले आईटी नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी मुद्रारहित लेनदेन जैसे कदम को कारगार बनाया जा सकता है।
4. साक्षरता एवं प्रशिक्षण अभियान– मुद्रारहित लेनदेन के मार्ग में सबसे बडी बाधा निरक्षरता को कम करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, साथ ही मुद्रारहित लेनदेन को बढावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अभियान भी चलाए जा सकते हैं।
5. बैंकिग सेवाओं में वृद्धि– देश में मुद्रारहित लेनदेन की गति बढाने के लिए सबसे पहले बैंकों की मात्रा एवं बैंकिंग सेवाओं में विस्तार करना अति आवश्यक है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए, एवं उन्हें सस्ती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6. साईबर सुरक्षा कानून की आवश्यकता– मुद्रारहित लेनदेन को पूर्णतः सुरक्षित बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि साईबर सुरक्षा कानून बनाए जिससे किसी भी व्यक्ति के मन में मुद्रारहित लेनदेन के प्रति किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना न रहे।
7. निजी क्षेत्र की भूमिका तय करना– मुद्रारहित अर्थव्यवस्था की ओर बढना कोई आसान काम नहीं है, यह किसी एक की जिम्मदारी नहीं है, न ही को सरकार अकेले इतना बढा कार्य कर सकती है, इसके लिए देश की निजी कम्पनियों को भी आगे आना होगा, विभिन्न आईटी कम्पनियों की भी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष– निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रारहित लेनदेन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह एक व्यक्ति, एक संस्था, एक कंपनी, अकेले सरकार के बस की बात नहीं है, इसके लिए सभी को आगे आना होगा। हर किसी को अपनी भूमिका समझनी होगी, और उसके तहत कार्य करना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जिसका फायदा किसी एक व्यक्ति को न मिलकर सभी को मिलेंगे। कैशलैस व्यवस्था से अर्थव्यवस्था मजबूती मिलेगी, रूपये की अंतराष्ट्रीय बाजार में रूपये की कीमत बढेगी। अर्थव्यवस्था की कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जायगीं। जिस प्रकार ग्रामीण भारत की जनता भी ईवीएम मशीन से वोट देने के लिए दक्ष हो चुकी है, गांव के बच्चे से लेकर बूढे तक मोबाईल फोन का आवश्यकतानुसार उपयोग करने लगे हैं, उसी तरह मुद्रारहित लेनदेन के लिए भी व्यक्ति एक समय बाद आदि हो जायेगें।

संदर्भ–

1. अग्रवाल ए. एन. : भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1977।
2. दत्त रूद्र एवं सुन्दरम के.पी.एम. : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली, 2012।
3. मिश्र एवं पुरी : भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिसिंग हाउस, मुंबई, (महाराष्ट्र), 2002।
4. घोष अलक : 'इण्डियन इकनॉमी, इट्स नेचर एण्ड प्राब्लम्स, कोलकाता।
5. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, 2015–16।
6. वार्षिक प्रतिवेदन, योजना आयोग, जुलाई 2015।

http://www.hindikiduniya.com
http://www.prabhatkhabar.com
http://www.punjabkesari.in
http://www.bbc.com/hindi/india
www.drishtiias.com
https://www.bhaskar.com
http://www.jagranjosh.com
http://www.amarujala.com